



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 396]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 4, 2016/कार्तिक 13, 1938

No. 396]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 4, 2016/KARTIKA 13, 1938

भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 2016

फा. सं.-आईडब्ल्यूटी-11011/45/2016-आईडब्ल्यूटी.—भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 82) की धारा 35 की उपधारा 2 खण्ड-(ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से बॉण्ड और अन्य ऋण प्रतिभूति जारी करने के लिए एतद् द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और उपयोजन.—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (ऋण प्रतिभूतियां जारी करना) विनियम, 2016 है।

(2) यह राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—(1) इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

- (क) "अधिनियम" से भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 82) अभिप्रेत है;
- (ख) "प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन गठित भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अभिप्रेत है;
- (ग) "समिति" से विनियम 5 के अधीन गठित निवेश समिति अभिप्रेत है;
- (घ) "ऋण प्रतिभूति" से अपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियां अभिप्रेत है, जिससे ऋणी बनता अथवा स्वीकार किया जाता है और जिसमें डिबेंचर, बॉण्ड और ऐसे अन्य किसी निकाय कॉर्पोरेट की प्रतिभूतियां अथवा कोई सांविधिक निकाय जिसका गठन तत्कालीन लागू नियम के अनुसार विधि द्वारा हुआ हो और जिसका प्रभार ऐसे किसी निकाय की परिसम्पत्ति पर हो अथवा न हो;

- (ड.) "निधि" से प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए बॉण्ड और अन्य ऋण प्रतिभूति से एकत्रित धन अभिप्रेत है;
- (च) "विवरणिका" से कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खण्ड (70) में परिभाषित विवरणिका अभिप्रेत है; और
- (छ) "प्रतिवेदन" से प्राधिकरण द्वारा ऋण प्रतिभूति के किसी प्रस्तावित मामले की आर्थिक व्यवहार्यता और प्रभाव पर निवेश समिति द्वारा दिए गए प्रतिवेदन अभिप्रेत है।

(2) अन्य सभी शब्द और वाक्यांश जिनका प्रयोग इन विनियमों में हुआ है किंतु जो परिभाषित नहीं हैं, उसका आशय अधिनियम अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) अथवा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) अथवा निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22) अथवा इसके अधीन बनाए गए नियम और विनियम से है।

### 3. बॉण्ड जारी करने के निबंधन.—प्राधिकरण -

- (क) ऋण प्रतिभूति जारी करके धन उधार लेगा, जिसकी सीमा केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी;
- (ख) ऐसे धन या निधि या संचयन का उपयोग पूरे तौर पर अथवा आंशिक रूप में अधिनियम के अधीन एक या अधिक कार्यों में किया जाएगा, जिसे प्राधिकरण समय-समय पर उचित समझेगा;
- (ग) प्राधिकरण अथवा किसी संस्था के नाम से खाता खोलेगा जिसका संचालन प्राधिकरण किसी एक या अधिक बैंकों के साथ प्राधिकरण के किसी एक या अधिक अधिकारियों अथवा प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किसी अभिकर्ता द्वारा करेगा;
- (घ) अटॉर्नी अथवा अभिकर्ताओं की नियुक्ति ऋण प्रतिभूति जारी करने के उद्देश्य से करके ऐसे अटॉर्नी अथवा अभिकर्ताओं के साथ उपबंध ऋण प्रतिभूति के संचालन और प्रबंधन के लिए करेगा;
- (ड.) कोई अन्य काम अथवा किसी अन्य गतिविधि में शामिल होगा जो उक्त कार्यों के कारण होगा; और
- (च) प्राधिकरण के अधिकारियों और अभिकर्ताओं तथा अटॉर्नियों द्वारा समय-समय पर ऋण प्रतिभूति का प्रचालन और प्रबंधन सहित निरीक्षण और अंकेक्षण करेगा।

### 4. निधि का सामान्य प्रयोजन.—प्राधिकरण, अधिनियम के अधीन सूचीबद्ध प्रयोजनों के लिए ऋण प्रतिभूति जारी करेगा, जो निम्नलिखित तक सीमित नहीं होगा, अर्थात् :-

- (क) फेयरवे का विकास,
- (ख) बाजों का निर्माण,
- (ग) टर्मिनल निर्माण और विकास,
- (घ) जलमार्ग परिवहन,
- (ड.) जलमार्गों हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाएं, और
- (च) परामर्शी और अनुसंधान सेवाएं

### 5. निवेश समिति.—(1) प्राधिकरण एक निवेश समिति का गठन करेगा जो यह सुनिश्चित करेगी कि प्राधिकरण द्वारा जारी ऋण प्रतिभूति विवेकपूर्ण और विधिक रूप से अनुपालनीय है।

(2) समिति का प्रयोजन - प्रतिभूति के माध्यम से एकत्र निधि का प्रबंधन करना और निवेश नीति को बनाने सहित उसकी देख-रेख करना होगा।

(3) समिति की संरचना निम्न प्रकार होगी :-

- (क) प्राधिकरण का उपाध्यक्ष समिति के अध्यक्ष होगा;
- (ख) प्राधिकरण के किसी सदस्य को प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;
- (ग) अध्यक्ष द्वारा एक कंपनी सचिव और दो परामर्शदाता (बाहरी) को नामनिर्दिष्ट ऐसे योग्य और ईमानदार व्यक्तियों में से किया जाएगा जिन्हें वित्तीय मामलों, वाणिज्य, वित्तीय विनियमन, कानून, अर्थशास्त्र और लोक प्रशासन के बारे में अच्छा ज्ञान और अनुभव होगा तथा कम से कम एक परामर्शदाता को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सामान्य बैंकिंग क्षेत्र में कम से कम 15 वर्षों का कार्य करने का अनुभव हो।
6. प्राधिकरण के अध्यक्ष के अनुरोध के 30 दिनों के भीतर समिति अपनी रिपोर्ट प्राधिकरण के सभी सदस्यों को सौंपेगी।
7. बैठकें.—प्राधिकरण में नियमित अंतराल पर होने वाली बैठकों के अनुसार ही बैठकें आयोजित की जाएगी अथवा जैसा समिति के अध्यक्ष आवश्यक समझेंगे।
8. समिति की बैठकों की कार्यसूची मद्रों के अनुमोदन के लिए समिति का अध्यक्ष उत्तरदायी होगा।
9. सुसंगत सामग्री के साथ कार्यसूची प्रत्येक बैठक से पहले समिति के सदस्यों को भेजी जाएगी।
10. सभी बैठकों के कार्यवृत्त मसौदा रूप में तैयार करके अध्यक्ष द्वारा समीक्षा कराई जाएगी जिसे समिति के सभी सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
11. समिति अपनी गतिविधियों की नियमित रूप से रिपोर्ट प्राधिकरण को देगी।
12. समिति के कार्य.—समिति-
- (क) ऋण प्रतिभूति को सभी संगत अधिनियमों, नियमों और विनियमों के साथ जारी कराना सुनिश्चित कराएगी;
- (ख) प्रस्तावित बॉण्ड और अन्य ऋण प्रतिभूति की आर्थिक व्यवहार्यता का मूल्यांकन करेगी;
- (ग) प्रस्तावित मामले की आर्थिक व्यवहार्यता के बारे में रिपोर्ट तैयार करके प्राधिकरण के सदस्यों को परिचालित करेगी;
- (घ) ऋण प्रतिभूति जारी करने के बारे में प्राधिकरण द्वारा की गई कार्रवाई से सम्बंधित सिफारिश करेगी; और
- (ङ.) ऐसे जारी के माध्यम से एकत्र निधि को विनियमित करेगी तथा सुनिश्चित करेगी कि ये उन प्रयोजनों के लिए उपयोग हुआ है जिसके लिए एकत्र किया गया था तथा उसके उचित उपयोग के बारे में सिफारिश करेगी।
13. बॉण्ड और अन्य ऋण प्रतिभूति जारी होने की प्रक्रिया.—प्राधिकरण सामान्य बहुमत से संकल्प पारित करके ऋण प्रतिभूति जारी करने के लिए अनुमोदन देगा।
14. (1) ऋण प्रतिभूति जारी करने के लिए जारी करते हुए संकल्प पारित करते हुए प्राधिकरण,-
- (i) संकल्प पारित करने से पहले ऐसे ऋण प्रतिभूति और अन्य प्रस्तावित बेंचर्स के बारे में समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करेगा।
- (ii) जहां प्राधिकरण समिति की सिफारिश के विरुद्ध निर्णय लेता है वहां ऐसा करने का कारण लिखित में देना होगा और ऐसे मामलों की सूचना प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में केंद्रीय सरकार को देनी होगी।
15. दोबारा बॉण्ड जारी करना और आपात शक्ति के मामले.—प्राधिकरण को दोबारा ऋण प्रतिभूति जारी करने की शक्ति होगी यदि ऐसा करना उचित होगा।
16. निधि के उचित उपयोग.—प्राधिकरण द्वारा एकत्र निधि भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण निधि भेजा जाएगा, जिसे अधिनियम के उपबंधों के अधीन बनाया गया है।
17. प्राधिकरण द्वारा एकत्र निधि का उपयोग विवरणिका में उल्लिखित उद्देश्य के लिए ही केवल होगा, जब तक कि केंद्रीय सरकार की लिखित अनुमति नहीं मिलेगी।
18. मामले के प्रयोजन को प्राप्त करने के पश्चात अधिशेष निधि, यदि कोई हो, का उपयोग समिति की सिफारिशों के अनुसार किया जाएगा और अधिनियम में दिए गए किसी प्रयोजन को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

19. **सदस्यों का दायित्व.**—समिति और इसके प्रत्येक सदस्य ऐसे सभी धन और निधि के लिए जबाबदेह होंगे जिसका निवेश होने के बाद प्राधिकरण के लेखा में दर्ज किया गया है और कोई सदस्य किसी बैंकर अथवा अटॉर्नी अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लापरवाही, दोष, भूलचूक के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे जिनके पास प्रतिभूति रखी अथवा जमा की गई है।
20. **लोक निर्गम.**—सभी ऋण प्रतिभूति के लोक निर्गम भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों के संगत उपबंधों के अनुसार अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुसार होगा।

[विज्ञापन III/IV/असा./287/16(306)]

त. साई अमृथा देवी, सचिव, भा.अ.ज.प्रा.

## INLAND WATERWAYS AUTHORITY OF INDIA

### NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd November, 2016

**F. No. IWT-11011/45/2016-IWT.**—In exercise of the powers conferred by clause (k) sub-section (2) section 35 of the Inland Waterways Authority of India Act, 1985 (82 of 1985), the Inland Waterways Authority of India, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations for the issue of bonds and other debt securities, as under, namely:-

**1. Short title, Commencement and application.**—(1) These regulations may be called the Inland Waterways Authority of India (Issue of Debt Securities) Regulations, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

**2. Definitions.**—(1) In these regulations, unless the context requires otherwise,-

- (a) “Act” means the Inland Waterways Authority of India Act, 1985 (82 of 1985)
- (b) “Authority” means the Inland Waterways Authority of India constituted under sub-section (1) of section 3 of the Act;
- (c) “Committee” means Investment Committee set up under regulation 5;
- (d) “Debt Securities” means a non-convertible debt securities which create or acknowledge indebtedness, and include debenture, bonds and such other securities of a body corporate or any statutory body constituted by or under any law for the time being in force whether constituting a charge on the assets of such body or not;
- (e) “funds” mean monies collected through the issue of bonds and other debt securities by the Authority;
- (f) “prospectus” means prospectus as defined in clause (70) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013);
- (g) “report” means the report made by the Investment Committee on the economic viability and impact of any proposed issue of debt securities by the Authority.

(2) All other words and expressions used but not defined in these regulations shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act or the Companies Act, 2013 (18 of 2013) or the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956) or the Depositories Act, 1996 (22 of 1996) or the rules and the regulations made thereunder.

**3. Terms for issue of bonds.**—The Authority shall –

- (a) borrow monies by means of issue of debt securities subject to such ceilings as may be deemed proper by the Central Government;
- (b) apply the whole or any part of the monies so raised, or the fund or accumulations thereto, to any one or more of the functions under the Act, as the Authority may, in its discretion, deem fit from time to time;

- (c) open an account in the name of the Authority or institutions run or conducted by the Authority with a bank or banks, operate such an account and give instructions to the bank and provide for opening and operation of such account by one or more of the officers of the Authority or by an agent appointed by the Authority;
- (d) appoint attorneys or agents for the purposes of issuing debt securities and authorise and enter into agreements with such attorneys or agents to operate and manage the debt securities;
- (e) do any other act or thing and exercise any other function or power which is incidental to the aforesaid functions; and
- (f) subject to the operation and management of the debt securities by the officers of the Authority and the agents and attorneys, inspected and audited at periodical intervals.

**4. General Purpose of the Funds.**—The Authority shall issue debt securities for the purposes listed under the Act and shall not be limited to the following, namely:-

- (a) development of fairway;
- (b) manufacturing of barges;
- (c) terminal construction and development;
- (d) waterway transportation;
- (e) infrastructural facilities for waterways; and
- (f) consultancy and research services.

**5. Investment Committee.**—(1) The Authority shall set up an Investment Committee to ensure that the debt securities issued by the Authority are prudent and legally compliant.

(2) The purpose of the Committee shall be to formulate and oversee the investment policies and management of the funds collected through the securities.

(3) The composition of the Committee shall be as follows:-

- (a) the Vice-Chairman of the Authority, shall be the Chairperson of the Committee;
- (b) one member of the Authority, to be nominated by the Chairman of the Authority;
- (c) one Company Secretary and two advisers (external) to be nominated by the Chairperson from amongst the persons of ability, integrity, and who have knowledge of, and adequate experience and capacity in dealing with problems relating to financial matters, commerce, financial regulation, law, economics and public administration, and also at least one adviser shall be a person having fifteen years' of general banking experience in a nationalised bank.

**6.** The Committee shall submit its report to all the members of the Authority within thirty days from the date of request by the Chairman of the Authority.

**7. Meetings.**—The meetings shall be held in conjunction with regularly scheduled meetings of the Authority, or as may be deemed necessary by the Chairperson of the Committee.

**8.** The Chairperson of the Committee shall be responsible for approving the agenda items for the meetings of the Committee.

**9.** An agenda, together with relevant materials, shall be sent to the members of the Committee in advance before each meeting.

**10.** Minutes for all meetings shall be prepared in draft form and reviewed by the Chairperson, and shall be concurred by the members of the Committee.

**11.** The Committee shall make regular reports of its activities to the Authority.

**12. Functions of the Committee.**—The Committee shall -

- (a) ensure the compliance of the issue of the debt securities with all relevant and applicable Acts, rules and regulations;
- (b) evaluate the economic viability of the proposed issue of bonds and other debt securities;

- (c) prepare and submit a report that shall be circulated to the members of the Authority, regarding the economic feasibility of proposed issue or reissue;
- (d) make recommendations as to the course of action to be taken by the Authority with regard to issue of debt securities; and
- (e) regulate the funds collected through such issue, ensure that they are used for the stated purpose for which they were collected, and make recommendations as to the proper use thereof.

**13. Procedure for issue of bonds, and other debt securities.**—The Authority shall pass a resolution to give its approval for issue of debt securities by a simple majority.

**14.** (1) While passing a resolution for issue of debt securities, the Authority shall,-

- (i) take into account the report submitted by the Committee regarding the issue of such debt securities and other proposed ventures before passing a resolution;
- (ii) where the Authority decides to go against the recommendations of the Committee, then it must provide the reasons for the same, in writing and such cases shall be reported to the Central Government at the end of each financial year.

**15. Re-issue of bonds and emergency powers of issue.**—The Authority shall have the power to re-issue and consolidate its debt securities, if it deems fit to do so.

**16. Proper use of funds.**—The funds collected by the Authority shall be debited to the Inland Waterways Authority of India Fund which has been set up under the provisions of the Act.

**17.** The funds collected by the Authority shall be used exclusively for the purpose stated in the prospectus of the issue and for no other purpose, except with the express permission of the Central Government.

**18.** After the purpose of the issue has been achieved, the surplus funds, if any, shall be used as per the recommendations of the Committee and for any of the purposes of the Authority as provided in the Act.

**19. Liability of the members.**—The Committee and every member shall be accountable for such monies and funds actually been invested after the same has been accounted in the Authority and a member shall not be responsible or accountable for any neglect, default, acts or omissions or commissions of any banker or attorney or other person with whom any securities have been deposited or kept.

**20. Public issue.**—Public issue of all the debt securities shall be in accordance with the relevant provisions of the regulations made by the Securities and Exchange Board of India or any other law for the time being in force.

[ADVT.-III/4/Ext./287/16(306)]

D. SAI AMUTHA DEVI, Secy., IWAI